



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2005/28 भाद्रपण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय सपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 अगस्त, 2005

संख्या 3429-35.—यह कि श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भाम्बला की मुहाल भाम्बला/463 में स्थित राज्य सरकार की भूमि खसरा नम्बर 183/1, रकबा तादादी 00-00-20 हेक्टेयर पर नाजायज कब्जा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। और यह कि दोषी प्रधान के विरुद्ध सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) बलदाड़ा के न्यायालय में मिसल संख्या 15/2003 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा वाले सुनवाई की गई तथा दिनांक 5-5-2004 को जारी फैसला के अन्तर्गत उक्त श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रोठल को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 183/1, तादादी 0-0-20 हेक्टेयर स्थित मुहाल भाम्बला/463 से हि० प्र० राजस्व अधिनियम, 1953 (एक्ट नम्बर 6 आफ 1954) की धारा 163(1) के अन्तर्गत वेदखल करने का आदेश जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान को हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व 122(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान ने दिनांक 9-8-2004 को प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर में व्यक्त किया कि उसने सरकारी भूमि से वेदखली के फैसले के विरुद्ध हि० प्र० राजस्व भूमि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अपील दायर की है तथा माननीय सिविल न्यायालय सरकाघाट में भी

निष्पत्ति हेतु अपील की है और उन दोनों मामलों में स्वयंसेवा जारी हुई है। लेकिन उप-मण्डलाधिकारी (ना०) सरकाघाट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दायर अपील का इस आधार पर निराकार किया जा चुका है कि उसने वर्णित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है। माननीय सिविल जज सरकाघाट के न्यायालय में दायर अपील संख्या 30/04 को भी दिनांक 14-12-2004 को जारी फैसले के अनुसार अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया है तथा इस मामले में सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) बलदाड़ा द्वारा दिनांक 5-5-2004 को जारी फैसले के विशद कोई भी अपील विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी जारी स्वयंसेवा शेष नहीं है।

और यह कि ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मुहाल भाम्बला/463 में स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 183/1, तादादी 0-0-20 हेक्टेयर पर नाजायज कब्जा के दोषी पाये गये हैं और उन्हें सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) बलदाड़ा द्वारा जारी फैसला दिनांक 5-5-2004 के अन्तर्गत उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया है। श्री राजेन्द्र सिंह प्रधान ने भी दिनांक 9-8-2004 को दिए अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि पर से नाजायज कब्जा छोड़ दिया है। इसलिए उक्त श्री राजेन्द्र सिंह पंचायत अधिकारी होने के लिए निरहित हो गए हैं।

अतः मैं, सुभाशीष पाण्डा, उपायुक्त मण्डो, जिला मण्डो (हि० प्र०), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज प्राधनियम, 1994 की धारा 122(2)(ii) तथा 131 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भाम्बला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डो (हि० प्र०) को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित करता हूँ तथा ग्राम पंचायत भाम्बला के प्रधान का पद भी रिक्त घोषित करता हूँ, और उन्हें यह निर्देश भी देता हूँ कि यदि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन, चल या अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत भाम्बला के सचिव को सौंप दें।

सुभाशीष पाण्डा,
भा० प्र० से०,
उपायुक्त, जिला मण्डो,
हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 4 अगस्त, 2005

संख्या: पी० सी० एच० एस० एम० एल० (4) 83-77-5088-92.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग वारे प्राप्त शिकायत पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से करवाई गई। खण्ड विकास अधिकारी रामपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत शोली द्वारा निम्न वर्णित निष्पादित विकास कार्यों का मौका पर मूल्यांकन करवाने पर पाया गया कि इन विकास कार्यों का मूल्यांकन व्यय राशि में कम प्रांका त्रिमके लिये श्रीमती जिवनी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत शोली दोषी है:—

क्रम संख्या	विकास कार्य का नाम	प्रांय	व्यय राशि	मूल्यांकित राशि	अधिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	नि० रास्ता कराल्टा अरोम	जे० आर० बाई०	15996.00	15279.00	771.00
2.	नि० रास्ता नोटो-कराल्टा	थोपरि	7500.00	1180.00	6320.00
3.	मौलिय ग्राम लोहटी	एम० जी० आर० बाई०	19580.00	11041.00	8539.00
4.	नि० रास्ता टाडा	जे० आर० बाई०	20000.00	8376.00	11624.00

यह कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 ता 4 पर वर्णित विकास कार्यों पर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा व्यय मूल्यांकित राशि से अधिक करके सरकारी धन का दुरुयोग किया है, जबकि प्रत्येक विकास कार्यों को पूर्ण करने व राशि के सही उपयोग का दायित्व प्रधान का होता है।

यह कि सौलिंग ग्राम लौहटी के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला परिवहन ने मु० 20,000.00 रुपये स्वीकृत किये थे, किन्तु पंचायत ने इस योजना के बजाए कुपह में खदेच व चौकी नामक स्थान से लौहटी गांव तक पैदल चलने योग्य रास्ते की मरम्मत का कार्य किया गया है, जबकि जांच रिपोर्ट में जो मस्ट्रोल जारी किये गये हैं वह मोलिंग ग्राम लौहटी के नाम से है, इस कार्य के निष्पादन पर व्यय 19580.00 रुपये उल्लेखित किये गये हैं, जबकि मूल्यांकन करने पर इसका मूल्यांकन 11041.00 रुपये आंका गया है। इस प्रकार इस कार्य पर मु० 8539 रुपये अधिक व्यय अनियमित रूप व मनमाने ढंग से किया गया है।

इस प्रकार उपर वर्णित निर्माण विकास कार्यों का मूल्य व्यय राशि में मु० 38241.00 रुपये कम आंका गया है, जिससे स्पष्ट होता है उपर्युक्त राशि का दुरुयोग पंचायत पदाधिकारियों द्वारा प्रधान की लापरवाही के कारण किया है। इसके अतिरिक्त प्रधान द्वारा स्वीकृत योजना को मनमाने ढंग में बदल कर राशि को अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है, जिसके लिये श्रीमती जिवनी देवी प्रधान ग्राम पंचायत बोधी पाई गई हैं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों को भली भांति निभाने में भी विफल रही हैं।

अतः मैं एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त जिमला, जिला जिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बनाओ नोटिस जारी करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों पर अपने स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर आपका लिखित उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हस्ताक्षरित/-
एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त,
जिमला, जिला जिमला।

